

केंद्र सरकार ने उत्तर प्रदेश के लिये 8 नई परियोजनाओं को मंजूरी दी

चर्चा में क्यों?

7 अक्टूबर, 2022 को उत्तर प्रदेश के एक सरकारी प्रवक्ता ने बताया कि केंद्र सरकार ने स्वच्छ गंगा परियोजना के लिये राष्ट्रीय मशिन के तहत राज्य में सीवरेज प्रबंधन सहित आठ नई परियोजनाओं को मंजूरी दी है।

प्रमुख बिंदु

- प्रवक्ता ने बताया कि राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मशिन की कार्यकारी समिति की 45वीं बैठक में सीवरेज प्रबंधन के लिये चार परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिनमें एक वाराणसी में भी है।
- इस परियोजना में अस्सी नल्ला (**Assi Nullah**) के दोहन के लिये 55 एमएलडी क्षमता के एसटीपी का निर्माण भी शामिल है। इस परियोजना की कुल अनुमानित लागत 09 करोड़ रुपए है।
- सरकार के प्रवक्ता ने कहा कि वाराणसी की परियोजना का लक्ष्य तीन नालों - अस्सी, सामने घाट और नखी से शून्य अनुपचारित नद्वहन के लक्ष्य को प्राप्त करना है।
- अन्य परियोजनाओं में 13 एमएलडी एसटीपी का निर्माण और मौजूदा संरचनाओं का नवीनीकरण शामिल हैं। मथुरा-वृंदावन की इन परियोजनाओं में यमुना नदी को प्रदूषित करने वाले 11 नालों को अवरुद्ध और मोड़ने की परिकल्पना की गई है। वृंदावन और मथुरा के कोसी कलां में सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट (एसटीपी) का निर्माण किया जाएगा।
- चार जिलों- हापुड़, बुलंदशहर, बदायूं और मरिजापुर में जैव-विविधता पार्क स्थापति करने की एक बड़ी परियोजना को भी मंजूरी दी गई है। इनके नाम हैं मरिजापुर में मोहनपुर बायोडायवर्सिटी पार्क, बुलंदशहर में रामघाट बायोडायवर्सिटी पार्क, हापुड़ में आलमगीरपुर बायोडायवर्सिटी पार्क और बदायूं में उझानी बायोडायवर्सिटी पार्क।
- प्रवक्ता ने कहा कि ये चारों स्थान गंगा नदी के बाढ़ के मैदानों पर स्थित हैं। प्रस्तावित पार्क गंगा के बाढ़ के मैदानों के साथ आरक्षित वनों का हिससा हैं और नदी के कायाकल्प एवं जैव-विविधता संरक्षण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे।
- जैव-विविधता पार्क देशी पौधों और जानवरों की प्रजातियों के संयोजन के साथ जंगल को अद्वितीय परदृश्य प्रदान करेंगे, जिससे एक कषेत्र में बनाए गए आत्मनिर्भर जैविक समुदायों का निर्माण होगा। गंगा जैव-विविधता पार्कों का समग्र परणाम पारस्थितिकी तंत्र सेवाओं, जैव-विविधता और गंगा नदी के कायाकल्प को बेसनि पैमाने पर बनाए रखने में मदद करेगा।